नईदुनिया

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को उज्जैन में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। उन्होंने विक्रमोत्सव-2024 में विक्रम पंचांग का विमोचन किया तथा रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में उद्योगपतियों-निवेशकों से वन-टू-वन चर्चा की।

प्रदेश के अन्य स्थानों में भी होंगी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव

मुख्यमंत्री ने दस हजार 64 करोड़ रुपए लागत की 61 इकाइयों का सिंगल क्लिक से किया भूमिपूजन और लोकार्पण

भोपाल (काप्र)।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि उज्जैन के रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के बाद प्रदेश में जबलपुर, रीवा और ग्वालियर में भी रीजनल कॉन्क्लेव आयोजित की जाएंगी। कॉन्क्लेव के दौरान ही औद्योगिक इकाईयों के लोकार्पण और भूमि पूजन भी किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत की जीडीपी ग्रोथ अनेक देशों को आश्चर्यचकित कर रही है। दुनिया हमारी तरफ उम्मीद की नजरों से देख रही है। डॉ. यादव ने कॉन्क्लेव में पधारे निवेशकों का स्वागत करते हुए कहा कि उद्योग जगत से सभी को अनेक आशाएं हैं। भारत के करीब 140 करोड़ नागरिक भी राष्ट्र के विकास में अहम योगदान दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री का नेतृत्व अभिनंदन के योग्य है। वे नई तकनीक का उपयोग करने के लिए प्रेरित करते हैं।

उन्होंने कहा कि उज्जैन के रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में अनेक औद्योगिक घरानों के प्रतिनिधि पधारे हैं। उज्जैन कॉन्क्लेव से करीब 1 लाख करोड़ के व्यवसाय और उद्योग का इतिहास बन रहा है। करीब 250 औद्योगिक परियोजनाओं में भूमि का आवंटन किया गया है। करीब 20 हजार से अधिक लोगों को नई इकाइयों से प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। कॉन्क्लेव के प्रारंभ में अनेक निवेशकों ने मध्यप्रदेश में निवेश संभावनाओं के संबंध में विचार व्यक्त किए। निवेशकों ने किए जाने वाले कार्य की जानकारी भी दी।

सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य कश्यप ने कहा प्रदेश में करीब 35 क्लस्टर स्थापित हैं। प्रदेश में क्षेत्र-विशेष में विशेष औद्योगिक उत्पादन की परंपरा रही है। निवेश को प्रोत्साहित करने वाली नीतियां हैं। एमएसएमई विभाग द्वारा 40 प्रतिशत कैपिटल सब्सिडी का मॉडल लोकप्रिय बनेगा। मुख्य सचिव श्रीमती वीरा राणा ने कहा कि मध्यप्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए प्रचुर संसाधन हैं। व्यापक वन क्षेत्र है। अनेक कृषि उत्पादनों ने मध्यप्रदेश अग्रणी है। कॉन्क्लेव के माध्यम से निवेश संभावनाओं को साकार करने में सहयोग मिलेगा।

इन्वेस्ट मध्य प्रदेश के अंतर्गत दो दिवसीय रीजनल इंडस्ट्री कांक्लेव के शुभारंभ अवसर पर प्रारंभ में मध्यप्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के एमडी चंद्रमौली शुक्ला ने शॉल और अंग वस्त्र द्वारा आमंत्रित निवेशकों का स्वागत किया। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव और औद्योगिक नीति एवं निवेश संवर्धन प्रमुख सचिव राघवेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि मध्यप्रदेश में निवेश की अपार संभावनाएँ हैं। प्रदेश के औद्योगिक परिदृश्य पर आधारित लघु फिल्म का भी प्रदर्शन किया गया। कॉन्क्लेव में संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास और धर्मस्व मंत्री धर्मेंद्र लोधी सहित जन-प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। अनेक जनप्रतिनिधि प्रदेश के विभिन्न स्थानों से वर्चुअली जुड़े।

283 इकाइयों को भूमि आवंटन-पत्र सौंपे

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कार्यक्रम के दौरान 283 इकाइयों को 508 हेक्टेयर भूमि के लिए आवंटन-पत्र प्रदान किये। इन इकाइयों द्वारा कुल 12 हजार 170 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश कर 20 हजार से अधिक लोगों को रोजगार दिया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने औद्योगिक इकाइयों के पदाधिकारियों को प्रतीक स्वरूप भूमि आवंटन-पत्र प्रदान किए। डॉ. यादव द्वारा पीएम कुसुम योजना में भी उद्योगपतियों को स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए। यह योजना नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण योजना है। डॉ. यादव ने कुल 10 हजार 64 करोड़ रुपए लागत की 61 इकाइयों का सिंगल क्लिक से भूमिपूजन और लोकार्पण किया। ये इकाइयां प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्थापित की गई हैं। साथ ही नई इकाइयां भी प्रारंभ हो रही हैं। डॉ. यादव ने विक्रम उद्योगपुरी जिला उज्जैन में भी नई इकाइयों का लोकार्पण किया।

प्रदेश के सभी विभागों के सहयोग से चलाया जाएगा जल-हठ अभियान

मुख्यमंत्री डॉ. यादव को जल संसाधन मंत्री सिलावट ने भेंट की कार्ययोजना

भोपाल (काप्र)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के प्रत्येक ग्राम में हर घर जल पहुंचाने के लिए वर्ष 2019 में जल जीवन मिशन शुरू किया गया। इस मिशन की पूर्ण सफलता के लिए प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के नेतृत्व में जल-हठ अभियान जन आंदोलन के रूप में चलाया जाएगा।

इसमें सरकार और समाज की भागीदारी से हर गांव, हर नगर में पुराने तालाबों एवं अन्य जल स्रोतों का उन्नयन, विकास, सौंदरीकरण, गहरीकरण कराया जाएगा तथा जल स्रोतों के आस पास किए गए अतिक्रमण को हटाकर वृक्षारोपण किया जाएगा। मुख्यमंत्री से गत दिवस मंत्रालय में जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने भेंट कर उन्हें इस अभियान की अवधारणा बताई तथा कार्य-योजना प्रस्तुत की। साथ ही अनुरोध किया कि सभी विभागों के सक्रिय सहयोग से प्रदेश के प्रत्येक ग्राम में जल-हठ अभियान को जन आंदोलन के रूप में चलाया जाए। डॉ.

यादव ने आश्वस्त किया कि पूरे प्रदेश में जल स्रोतों के संरक्षण एवं जल संवर्धन को जन आंदोलन का रूप दिया जाएगा। श्री सिलावट ने कहा कि अभियान के अंतर्गत जल स्रोतों के अतिक्रमणों को प्राथमिकता से हटाया जाएगा। प्रदेश के तालाबों एवं अन्य जल स्रोतों में अतिक्रमण से उनका कैचमेंट एरिया समाप्त होता जा रहा है, जिससे जल स्रोतों में प्रदूषण की समस्या बढ़ रही है तथा सिंचाई एवं पीने का पानी कम हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्र के छोटे-छोटे नदी नालों में पहले वर्ष भर जल संरक्षित रहता था, किंतु ये नदी-नाले अब समाप्त प्राय हो गए हैं। वर्षा के जल को संरक्षित करने एवं भूजल उन्नयन के लिए इन्हें पुनर्जीवित करना अत्यंत आवश्यक है। मंत्री श्री सिलावट ने बताया कि जल-हठ अभियान के अंतर्गत प्रदेश के सभी जिलों में प्राकृतिक जल स्त्रोतों, तालाबों के पुनर्जीवन कार्य के लिए उन्हें चिन्हित कर योजना बनाई जाएगी।

सरकारी स्कूलों में गणवेश प्रदाय करने के संबंध में निर्देश

भोपाल (काप्र)। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को गणवेश उपलब्ध कराने के संबंध में राज्य शिक्षा केन्द्र ने जिला कलेक्टर्स को पत्र लिखा है।

प्रदेश के 22 जिलों में गणवेश वितरण की कार्यवाही राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा की जा रही है। स्व-सहायता समूहों को आगामी 15 मार्च तक नि:शुल्क गणवेश उपलब्ध कराये जाने के निर्देश राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा दिये गये है। प्रदेश के 30 जिलों में कक्षा 1 से 8 तक के शासकीय स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को गणवेश की राशि विद्यार्थियों के खातों में जमा कराई जायेगी। प्रदेश के सीएम राईज स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को गणवेश विद्यालय द्वारा प्रदाय किये जायेंगे। इन जिलों में विद्यार्थियों के बैंक खाते में गणवेश की राशि 600 रूपये प्रतिदर से प्रदाय की जायेगी। सरकारी स्कूलों में गणवेश का वितरण सुव्यवस्थित तरीके से हो सके, इसके लिये शिक्षा पोर्टल में गणवेश वितरण प्रबंधन मॉड्यूल तैयार किया गया है। शासकीय शालावार छात्रों की सत्यापित सूची विकासखंड स्तर पर उपलब्ध कराये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं।

प्रदेश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम में कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों में सत्र 2024-25 में नि:शुल्क प्रवेश ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। आवेदन के बाद आवेदन की पावती और मूल दस्तावेज लेकर चयनित जनशिक्षा केन्द्र पर 5 मार्च तक सत्यापन कराने के लिये कहा गया है। नियत तारीख के बाद सत्यापन न होने की दशा में आवेदन स्वत: ही निरस्त हो जायेगा।

अतिशेष प्रशिक्षण अधिकारियों को अन्य व्यवसायों में समायोजित करने के निर्देश

भोपाल (काप्र)।

कौशल विकास एवं रोजगार संचालनालय में पदस्थ अतिशेष एवं बंद हुए व्यवसायों के प्रशिक्षण अधिकारियों को उनकी योग्यता के आधार पर अन्य व्यवसायों में समायोजन का अवसर प्रदान करने के लिये कार्य-योजना बनायें।

कौशल विकास एवं रोजगार राज्य मंत्री गौतम टेटवाल ने यह निर्देश विभागीय योजनाओं की समीक्षा के दौरान दिये। उन्होंने कहा कि सभी आईटीआई में प्रशिक्षण की गुणवत्ता सुधार के लिये जरूरी कदम उठायें। आकांक्षी जिलों में संचालित आईटीआई के उन्नयन के लिये विस्तृत कार्य-योजना बनाई जाये। विकासखण्डों में संचालित आईटीआई में जरूरी उपकरण एवं सुविधाएँ उपलब्ध करायें। आईटीआई में अध्ययनरत प्रशिक्षणार्थियों को उत्कृष्ट आईटीआई में भ्रमण करवायें। शासकीय आईटीआई में उद्योगों के माध्यम से ऑन द जॉब ट्रेनिंग को बढ़ावा देने के लिये कार्य-योजना बनायें।

श्री टेटवाल ने कहा कि संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क भोपाल में संचालित पाठ्यक्रम से अवगत कराने आईटीआई प्रशिक्षणार्थियों को यहाँ 4-5 दिनों के लिये प्रशिक्षण दिया जाये। नवीन स्वीकृत आईटीआई के भूमि का चयन एवं भवन निर्माण की कार्यवाही शुरू करें। रिक्त उच्च पदों के प्रभार देने की कार्यवाही भी करें।

श्री टेटवाल ने कहा कि निर्धारित समय-सीमा में कार्य नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने आईटीआई एवं अन्य कार्यालयों में 3 से अधिक वर्षों तक एक ही स्थान पर पदस्थ कर्मचारियों को बदलने का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश भी दिये। आईटीआई के निरीक्षण का रोस्टर बनायें। श्री टेटवाल ने ग्लोबल स्किल पार्क का निर्माण कार्य जल्द पूरा कराने के निर्देश दिये। साथ ही यहाँ की भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के निर्देश भी दिये। बैठक में परियोजना संचालक श्री गौतम सिंह और संचालक कौशल विकास एवं रोजगार श्री सोमेश मिश्रा एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

प्रसिद्ध फोनोसर्जन डॉ. मेनन कल भोपाल में करेंगे सर्जरी

डॉ. जयकुमार मेनन

डॉ. एस.पी. दुबे

भोपाल। देश के प्रसिद्ध फोनोसर्जन जयकुमार मेनन रविवार को भोपाल में खराब आवाज को ठीक करने की सर्जरी करेंगे और प्रोफेशनल आवाज की देखभाल कैसे करें इस पर व्याख्यान देंगे। कार्यक्रम के आयोजक सुविख्यात ईएनटी सर्जन डॉ. एसपी दुबे ने बताया कि डॉ. मेनन एक दिन की वर्कशॉप दिव्य एडवांस्ड ईएनटी क्लीनिक में करेंगे जिसमें देश भर के जाने-माने ईएनटी सर्जन भाग लेंगे। इस अवसर पर प्रोफेशनल आवाज को ठीक रखें इस विषय पर भी चर्चा रखी गई है। डॉ. मेनन फोनोसर्जन्स ऑफ इंडिया के संस्थापक उपाध्यक्ष तथा पूर्व अध्यक्ष भी हैं। डॉ. दुबे ने बताया कि यह पहला अवसर है जब डॉ. मेनन अपनी तरह के इस विशेष आयोजन में शामिल हो रहे हैं। इस अवसर वे अपने चिकित्सा क्षेत्र के व्यापक अनुभव भी साझा करेंगे।

उत्कृष्ट कार्य करने वाली रेडक्रॉस ईकाईयों को किया गया सम्मानित

पीड़ितों की सेवा ही परमेश्वर की सच्ची सेवा : राज्यपाल

भोपाल (काप्र)।

राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा है कि पीड़ित मानवता की सेवा ही परमेश्वर की सच्ची सेवा है। उन्होंने कहा कि रेडक्रॉस द्वारा प्रदेश में किए जा रहे कार्य, मानवता की सेवा का माध्यम है।

जिला ईकाईयाँ सेवा के इस अभियान में बेहतर से बेहतर कार्य करने का प्रयास करें। रेडक्रॉस गरीबों और पीड़ितों तक चिकित्सा सेवायें पहुँचाने के लिए विशेष कदम उठाएं। श्री पटेल आज राजभवन के सांदीपनि सभागार में स्टेट रेडक्रॉस की वार्षिक साधारण सभा को संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल के प्रमुख सचिव संजय कुमार शुक्ल और रेडक्रॉस सोसाईटी के चेयरमेन डॉ. गगन कोल्हे भी मौजूद थे। राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि समाज के ग़रीब, वंचित और ज़रूरतमंदों तक स्वास्थ्य सेवायें पहुँचाने में रेडक्रॉस की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है। रेडक्रॉस शासकीय चिकित्सालयों में आधुनिक उपचार संसाधनों की आपूर्ति में सहयोग के लिए समृद्ध वर्ग को भी जोड़ें। नए कॉलेजों को युवक रेडक्रॉस में पंजीकृत करने का अभियान चलायें। युवाओं को भी सामाजिक सरोकारों के लिए

संस्कारित कर योगदान देने के अवसर उपलब्ध कराए। उन्होंने कहा कि रेडक्रॉस द्वारा टी.बी. जागरूकता के अभियान में निक्षय मित्र बनाने का कार्य सराहनीय हैं। उन्होंने सिकल सेल एनीमिया के रोगियों की मदद के लिए जन सहयोग का अभियान चलाए जाने की आवश्यकता बताई।

कार्यक्रम में राज्यपाल का आत्मीय स्वागत और स्मृति चिन्ह देकर अभिनंदन किया गया। राज्यपाल ने विभिन्न ज़िलों की रेडक्रॉस ईकाईयों को उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित भी किया। राज्य रेडक्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष डॉ. गगन कोल्हे ने स्वागत भाषण दिया। जनरल सेक्रेटरी प्रदीप त्रिपाठी ने सोसाइटी की गतिविधियों की जानकारी दी। कोषाध्यक्ष शशांक श्रीवास्तव ने सोसाइटी के वित्तीय प्रबंधन का ब्यौरा दिया। वाइस चेयरमैन भारत झंवर ने आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में ऑल इण्डिया ब्लड बैंक की डायरेक्टर श्रीमती वंशी सिंह, वरिष्ठ अधिकारी, राज्य और जिला रेडक्रॉस समितियों के सदस्य भी उपस्थित थे।